हिन्दी पाक्षिक

सेमन्या कणवघाटी

RNI No.: UTTHIN/2013/54659

वर्ष-13 अंक-11 हरिद्वार, बुधवार, 15 अप्रैल, 2026 मूल्य-दो रूपया मात्र पृष्ठ-8

खत्म हुआ इंतजार, अब ढाई घंटे में दिल्ली दरबार

देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण

देहरादून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड, गढ़ी कैंट में आयोजित समारोह में 210 किमी लंबे, दिल्ली -देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का रिमोट बटन दबाकर लोकार्पण किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गढ़ी कैंट तक 12 किलोमीटर लंबे रोड शो में प्रतिभाग करने के साथ ही डाटकाली मंदिर में दर्शन करने के उपरांत पूजा भी की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़ी कैंट में आयोजित, समारोह में अपने संबोधन की शुरुआत देशवासियों को बैसाखी और बिहू पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तराखंड में स्थित पवित्र चार धामों की भी यात्रा शुरु होने वाली है, जिसका देशभर के आस्थावान लोग प्रतीक्षा करते हैं। दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने से चारधाम के यात्रियों को भी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना के 26वें प्रवेश कर चुका है, अब राज्य की प्रगति में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस-वे भी शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ साल पहले उन्होंने बाबा केदार की धरती पर अनायास ही कहा था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड के नाम होने जा रहा है, उन्हें यह देखकर बेहद खुशी हो रही है कि डबल इंजन वाली सरकार की नीतियों और उत्तराखंड के लोगों के परिश्रम से उत्तराखंड तेजी से इस राह पर बढ़ रहा है।

उत्तराखंड ने देश को दिखाई राह: प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ बीआर अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि बीते एक दशक से उनकी सरकार ने जो भी निर्णय लिए वो देश के संविधान की गरिमा को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और देश से माओवाद खत्म होने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि, उत्तराखंड ने संविधान की भावना के अनुरूप, समान नागरिक संहिता लागू कर, पूरे देश को नई राह दिखाई है।

उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों को न्याय पूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित रहा है, केंद्र सरकार भी इसी भावना के साथ हर गरीब को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि देश का संतुलित विकास, सबको सुविधा और सबकी समृद्धि ही सामाजिक न्याय का माध्यम बन सकती है। इसलिए बाबा साहेब भी औद्योगिकरण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भरपूर वकालत करते थे।

सड़कें बनेगी भविष्य की रेखा: प्रधानमंत्री ने देश के विकास में सड़क, रेलवे, रोपवे और वाटरवे की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि कुछ लोग, भविष्य जानने के लिए हाथ की रेखाओं को दिखाने के लिए ज्योतिष शास्त्र की शरण में जाते हैं। आज इसी तरह सड़कें, राष्ट्र की भाग्य रेखाएं बनती जा रही हैं। उन्होनें कहा कि बीते एक दशक से सरकार विकसित भारत के लिए ऐसी ही भाग्यरेखाओं के निर्माण में जुटी हुई है। ये भाग्य रेखाएं, सिर्फ आर्थिकी का आधार नहीं बनेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी की समृद्धि की गारंटी भी बनेगी और यही मोदी की गारंटी भी है। उन्होंने कहा कि बीते एक दशक में सरकार ने इन विकास रेखाओं के निर्माण में अभूतपूर्व निवेश किया है। वर्ष 2014 तक, पूरे देश के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर दो लाख करोड़ भी खर्च नहीं हो पाते थे, जबकि आज यह राशि छह गुना अधिक बढ़कर 12 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। इस दौरान अकेले उत्तराखंड में ही, सवा दो लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़कों के इंतजार में पीढ़ियां बूढ़ी हो जाती थी, आज डबल इंजन की सरकार के कारण गांव गांव सड़क पहुंच रही है। इससे वीरान गांव फिर जीवंत हो रहे हैं। चारधाम महामार्ग परियोजना, रेल परियोजना, केदारनाथ, हेमकुंड रोपवे जैसे परियोजनाएं उत्तराखंड की भाग्य रेखाएं बन रही हैं। नए भारत में स्पीड और स्केल

- शेष पृष्ठ 8 पर ...

श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी

बैसाखी पर्व पर गंगा स्नान का सिलसिला जारी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद

हरिद्वार । धर्मनगरी हरिद्वार में बैसाखी पर्व आज भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरकी पौड़ी समेत तमाम गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्यलाभ अर्जित कर रहे है। बैसाखी और सद्भावना सम्मेलन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को जोन और 10 जोन और 33 सेक्टर में बांटा गया है। मेला क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पीएसी, बीडीएस, और जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है।

हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी समेत सभी अधिकारी मौके पर तैनात रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वहीं ग्रह नक्षत्रों के अनुसार आज सुबह नौ बजकर 41 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए आज भी बैसाखी पर्व पर दूर दराज से आए श्रद्धालु गंगा स्नान और दान पुण्य कर पुण्यलाभ कमा रहे हैं। मान्यता है कि बैसाखी के दिन सूर्य, मकर राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं।

ज्योतिष के अनुसार सूर्य की दिशा में परिवर्तन के साथ ऋतु में भी परिवर्तन होता है। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी बताते है कि बैसाखी ख पूर्णिमा के दिन गंगा पूजन, सूर्य पूजन, गंगा स्नान और दान पुण्य करने से मनुष्य के जीवन मे सुख समृद्धि आती है। आज के दिन 1000 वर्षों तक तपस्या का पुण्य फल केवल गंगा स्नान से मिलता है। इसके साथ ही सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में एक मन सोना दान करने के बराबर भी पुण्यफल गंगा स्नान से ही प्राप्त हो जाता है। बताया कि गंगा स्नान के बाद अपने तीर्थ पुरोहित और गुरुओं को मौसमी फल और रस वाले पात्र दान करने से भी पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पर्व के पावन अवसर पर हर की पैड़ी पर मंगलवार सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

तड़के से ही देश के हर कौने से आए श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचने लगे और पूरे क्षेत्र में गंगा मैया की जय के जयकारों गूंजने लगा।

श्रद्धालुओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। इसके साथ ही हरकी पैड़ी पर ही हवन पूजा कर सुख शांति की कामना की। पहाड़ों से आई कई देव डोलियां को भी गंगा स्नान कराया गया। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया।बैसाखी पर्व के चलते हरिद्वार में विशेष उत्साह देखने को मिला। बाजारों में भी रौनक बढ़ी रही और अन्य सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना का दौर चलता रहा। कुल मिलाकर आस्था, उत्साह और श्रद्धा के संगम के बीच बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बैसाखी पर्व और सद्भावना सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिनभर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा, ठोस यातायात प्लान लागू किया गया है।

कांग्रेस ने मनाई बाबा साहेब की 135वीं जयंती

हरिद्वार । कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती पर दो अलग-अलग स्थानों पर गोष्ठी का आयोजन किया। महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मायापुर स्थित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं, ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च्छ स्थित अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉ. आंबेडकर के योगदान को याद कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मायापुर कार्यालय में जिला महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग एवं स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मुरली मनोहर ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान निर्माण के माध्यम से पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया।

वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा और महानगर कांग्रेस महासचिव राजीव भार्गव ने कहा कि डॉ. आंबेडकर का जीवन हमें शिक्षा के महत्व को समझाता है। इस दौरान पार्षद हिमांशु गुप्ता, यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव उत्कर्ष वालिया, श्रमिक नेता वीरेंद्र श्रमिक, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नितिन तेश्वर, एससी-एसटी कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अमित चंचल, अशोक गुप्ता, धनीराम शर्मा, अरुण चौहान, विकास सिंह, प्रहलाद सिंह चौहान, भरत ठाकुर आदि मौजूद रहे। वहीं, ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च्छ स्थित आंबेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी बलजीत सिंह और रमेश चंद कटारिया ने कहा कि बाबा साहब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो समाज के उत्थान का मूल मंत्र है। इस दौरान अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष तीर्थ पाल रवि, मनोज सैनी, अशोक शर्मा, पार्षद सुनील कुमार, संजय सैनी, पुनीत कुमार, अजय कुमार मुखिया, अशोक कुमार, ममता सिंह, पूरन सिंह, दिनेश दुबे आदि मौजूद रहे।

सम्पादकीय

ऊर्जा संकट से कैसे बाहर निकलें मजदूर

आज जब देश ऊर्जा संकट की चुनौती से जूझ रहा है, उसका सबसे गहरा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ रहा है जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है—मजदूर वर्ग। महंगी बिजली, बढ़ते ईंधन दाम और अनिश्चित रोजगार ने मजदूरों की रोजमर्रा की जिंदगी को और कठिन बना दिया है। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि मजदूर इस संकट से कैसे बाहर निकलें और सरकार व समाज उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। ऊर्जा संकट केवल बिजली की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कोयला आपूर्ति, अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों, और नीतिगत कमजोरियों से भी जुड़ा है। जब उद्योगों की लागत बढ़ती है, तो सबसे पहले असर मजदूरों की मजदूरी और रोजगार पर पड़ता है। कई छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर हैं, जिससे मजदूरों का पलायन तेज हो रहा है। ऊर्जा संकट के बीच मजदूरों का शहरों से गांवों की ओर पलायन ने गहरी चिंता पैदा कर दी है। देश में बढ़ते ऊर्जा संकट ने केवल उद्योगों और अर्थव्यवस्था को ही प्रभावित नहीं किया है, बल्कि इसका सबसे बड़ा असर आम मजदूर वर्ग पर पड़ रहा है। बिजली की कमी, महंगी ऊर्जा और घटते औद्योगिक उत्पादन के कारण शहरों में रोजगार के अवसर लगातार सिकुड़ रहे हैं। ऐसे हालात में मजदूरों का शहरों से गांवों की ओर पलायन फिर से तेज होता दिख रहा है। ऊर्जा संकट का सीधा असर फैक्ट्रियों और छोटे उद्योगों पर पड़ा है। कई उद्योग या तो बंद हो गए हैं या सीमित क्षमता पर काम कर रहे हैं। इससे दिहाड़ी मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की आय पर गहरा असर पड़ा है। जब शहरों में काम नहीं मिलता, तो मजदूरों के सामने अपने गांव लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यह स्थिति हमें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुए बड़े पैमाने के पलायन की याद दिलाती है, जब लाखों मजदूर शहरों से अपने गांवों की ओर लौट गए थे। हालांकि मौजूदा संकट उतना अचानक नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव धीरे-धीरे उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं गांवों में लौटने के बाद मजदूरों को रोजगार की गारंटी नहीं मिलती। कृषि पहले से ही सीमित संसाधनों पर निर्भर है और सभी के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दे सकती। ऐसे में ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ने का खतरा है। इससे सामाजिक और आर्थिक असंतुलन और गहरा सकता है। सरकार के सामने चुनौती है कि वह ऊर्जा संकट का स्थायी समाधान निकाले और साथ ही शहरी रोजगार को बचाए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, छोटे उद्योगों को राहत देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना समय की मांग है।मजदूरों का यह पलायन केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि एक मानवीय संकट भी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका असर देश के विकास की गति पर भी पड़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां आर्थिक प्रगति की गाथाएं अक्सर सुनाई जाती हैं, वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसकी रोज़मर्रा की जिंदगी आज भी संघर्षों से भरी हुई है। मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं — यह कथन सुनने में अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई इससे बहुत दूर नहीं है। जब तक मजदूर को स्थायी रोजगार, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक उसकी स्थिति में ठोस सुधार संभव नहीं है। मजदूर के पास चूल्हे जलाने तक के पैसे नहीं — यह न तो पूरी तरह फ़साना है, न ही हर जगह की सच्चाई। यह उस कड़वी हकीकत का प्रतीक है, जिसे हम अक्सर आंकड़ों और विकास के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं। समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है कि मजदूर वर्ग को सिर्फ योजनाओं का लाभ ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिले। तभी असली विकास संभव होगा। देश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों मजदूर आज भी अस्थिर आय, महंगाई और सामाजिक सुरक्षा की कमी से जूझ रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर की कमाई अक्सर इतनी सीमित होती है कि वह सिर्फ दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर पाता है। ऐसे में अगर एक दिन भी काम न मिले, तो चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। महंगाई ने इस संकट को और गहरा किया है। रसोई गैस, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि ने गरीब परिवारों की कमर तोड़ दी है। कई जगहों पर आज भी लोग लकड़ी या कंडे से खाना बनाने को मजबूर हैं। हालांकि यह भी सच है कि सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं—मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना, मनरेगा जैसी योजनाएं मजदूरों को राहत देने का प्रयास करती हैं। इन योजनाओं से कई परिवारों की स्थिति में सुधार भी आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं हर जरूरतमंद तक पूरी तरह पहुंच पा रही हैं? अक्सर भ्रष्टाचार, जानकारी की कमी और व्यवस्थागत खामियों के कारण कई मजदूर इन लाभों से वंचित रह जाते हैं। समस्या केवल आय की नहीं, बल्कि असमानता और अवसरों की भी है। पहला समाधान यह हो सकता है कि सरकारी हस्तक्षेप यानी सरकार को सस्ती बिजली और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी और राहत पैकेज देने चाहिए। ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। दूसरा वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना । सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों को अपनाना इस संकट का स्थायी समाधान हो सकता है। अगर मजदूरों को सोलर पैनल जैसी सुविधाएं सस्ती दरों पर मिलें, तो वे अपनी ऊर्जा जरूरतें खुद पूरी कर सकते हैं। तीसरा रोजगार के नए अवसर पैदा करना ऊर्जा क्षेत्र में ही रोजगार सृजन किया जा सकता है—जैसे सोलर इंस्टॉलेशन, बैटरी मेंटेनेंस आदि। इससे मजदूरों को नया कौशल और काम मिलेगा। चौथा सामाजिक सुरक्षा यानी मजदूरों के लिए राशन, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि वे संकट के समय भी सम्मानजनक जीवन जी सकें। ऊर्जा संकट केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ाने वाला मुद्दा भी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा मजदूर वर्ग को ही भुगतना पड़ेगा।

बंगाल की अस्मिता को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती हैं ममता

अजय कुमार

पश्चिम बंगाल की चुनावी जमीन पर तनाव भरा माहौल छाया हुआ है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करने के सपने बुन रही है। इस बार की लड़ाई 2021 वाली जंग से बिल्कुल अलग नजर आ रही है। पहले के चुनावों में हिंसा का तांडव देखने को मिला था, जहां दंगाइयों को खुला संरक्षण मिला। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कानून की सख्ती ने उपद्रवियों की हिम्मत तोड़ दी है। अर्धसैनिक बलों के जवान हर कोने में मुस्तैद हैं, जो किसी भी तरह की गुंडागर्दी को कुचलने को तैयार हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इन बदलावों से ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क उठा है। वे खुद को पीड़ित साबित करने की कोशिश कर रही हैं, जो उनकी पुरानी चाल है। चुनावी जंग की शुरुआत होते ही पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उत्तेजना का माहौल बन गया। 2021 में जो दृश्य देखे गए थे, वे भयानक थे। तब तृणमूल के कार्यकर्ताओं ने हिंसा का सहारा लिया। रामनवमी के जुलूस पर हमले हुए, घरों को आग लगाई गई, और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। पुलिस ने आंखें मूंद लीं। लेकिन इस बार सब कुछ अलग है। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों को भारी संख्या में तैनात किया। ये जवान सीधी कार्रवाई करने से नहीं हिचकते। कोलकाता के एक इलाके में जब गुंडों ने मतदान केंद्र के पास उपद्रव मचाने की कोशिश की, तो जवानों ने तुरंत लाठियां भांजीं। पांच उपद्रवी घायल हो गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इससे आसपास का इलाका शांत हो गया। एक अन्य घटना में दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव में तृणमूल समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को घेर लिया। लेकिन अर्धसैनिक बल ने फटाक से हस्तक्षेप किया। हवा में गोली चलाई गई और गुंडे भाग खड़े हुए। इन उदाहरणों से साफ है कि कानून अब किसी की सुनता नहीं।

ममता बनर्जी को ये सख्ती रास नहीं आ रही। वे हर मौके पर चिल्ला रही हैं कि केंद्र चुनाव में दखल दे रहा है। एक रैली में उन्होंने रोते हुए कहा कि उनके राज्य पर हमला हो रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि अर्धसैनिक बल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहे हैं। वे तृणमूल के गुंडों पर भी उतनी ही सख्ती दिखा रहे हैं जितनी किसी और पर। उदाहरण के तौर पर हावड़ा में एक तृणमूल नेता ने पुलिस अधिकारी को धमकाया। अधिकारी ने शिकायत की, तो अर्धसैनिक बल ने उस नेता को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। ममता ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। वे कहती हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में दर्ज है कि इस बार हिंसा की घटनाएं 2021 के मुकाबले 70 प्रतिशत कम हुई हैं। मतदान केंद्रों पर कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ। यह सब अर्धसैनिक बल की मौजूदगी का नतीजा है।

चुनाव आयोग भी पीछे नहीं हट रहा। आयोग ने हर जिले में विशेष टीम गठित की हैं। ये टीमें रात-दिन गश्त कर रही हैं। एक बार उत्तर दिनाजपुर में एक जज को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। जज निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी कर रहे थे। कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे कि जज पक्षपाती हैं। लेकिन अर्धसैनिक बल ने तुरंत पहुंचकर जज को सुरक्षित निकाला और आठ लोगों को पकड़ लिया। जज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अगर ये जवान न होते, तो हालात बिगड़ जाते। इसी तरह मालदा में एक पुलिस अधिकारी को धमकी मिली। अधिकारी मतपेटियों की गिनती करवा रहे थे। गुंडों ने उन्हें घेरा, लेकिन जवानों ने डंडों की बौछार कर दी। तीन गुंडे अस्पताल पहुंचे। ये उदाहरण बताते हैं कि अब कानून का राज है। जज और अधिकारी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पहले वे डरते थे, अब वे बेधड़क काम कर पा रहे हैं।

ममता बनर्जी इस स्थिति से तिलमिला रही हैं। उनका पारा चढ़ा हुआ है। वे हर सभा में केंद्र को कोसती हैं। कहती हैं कि दिल्ली वाले उनके राज्य को बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनकी यह चाल उल्टी पड़ रही है। जनता अब उनकी नाटकबाजी समझ रही है। विक्टिम कार्ड खेलने का उनका तरीका पुराना है। 2021 में भी उन्होंने यही किया था। तब हिंसा के बाद वे रो-रोकर टीवी पर आईं और खुद को मां बताते हुए वोट मांगे। कहा कि बेटे को बचाओ। इस बार भी वही फॉर्मूला अपना रही हैं। कोलकाता की एक सभा में वे घुटने मोड़कर बैठ गईं। आंसू बहाते हुए बोलीं कि उन्हें कुर्सी से हटाने की साजिश चल रही है। उनके समर्थक चिल्लाने लगे। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता हंस पड़े। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो वायरल हो गए। लोग कह रहे हैं कि यह नौटंकी है। एक और उदाहरण लीजिए। जब अर्धसैनिक बल ने उनके एक विधायक को पकड़ा, तो ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कहा कि विधायक निर्दोष हैं, उन पर झूठा केस बनाया गया। लेकिन जांच में पता चला कि विधायक ने ही हिंसा भड़काई थी। आयोग ने उसे अयोग्य घोषित कर दिया। ममता ने फिर विक्टिम बनने की कोशिश की। कहा कि न्याय व्यवस्था उनके खिलाफ है इसके अलावा ममता भक्तों को भड़काने से नहीं चूक रही हैं। वे कहती हैं कि बंगाल की बेटी पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन जनता जाग चुकी है। 2021 में वे सफल रहीं क्योंकि हिंसा का डर था। अब डर खत्म हो गया। अर्धसैनिक बल ने गुंडों की कमर तोड़ दी। एक सर्वे में सामने आया कि 60 प्रतिशत मतदाता शांतिपूर्ण चुनाव से खुश हैं। वे ममता की गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं। उदाहरण स्वरूप, आसनसोल में एक महिला मतदाता ने कहा कि पहले डर लगता था, अब बेझिझक वोट दे सकी। इसी तरह पुरुलिया के एक युवक ने बताया कि उसके भाई को 2021 में पीटा गया था। इस बार सब शांत रहा। ये बदलाव ममता के लिए खतरे की घंटी हैं। उनका विक्टिम कार्ड अब फेल हो रहा है। वे खुद को पीड़ित बताकर वोट बटोरना चाहती हैं, लेकिन लोग सच्चाई जान चुके हैं।चुनावी माहौल में और भी रोचक घटनाएं घटीं। बांकुरा जिले में तृणमूल ने फर्जी वोटिंग की कोशिश की। लेकिन चुनाव आयोग की टीम ने पकड़ लिया। अर्धसैनिक बल ने मौके पर छापा मारा। 20 लोग गिरफ्तार हुए। ममता ने इसे साजिश कहा। लेकिन सबूतों ने उन्हें झूठा साबित कर दिया। हुगली में एक जज को धमकी भरा फोन आया। जज ने आयोग को सूचना दी। जवानों ने फोन करने वाले को ट्रेस कर पकड़ लिया। वह तृणमूल का स्थानीय नेता निकला। ममता ने चुप्पी साध ली। इन घटनाओं से साफ है कि सख्ती काम कर रही है। उपद्रव करने वालों को सबक मिल रहा है। जज और अधिकारी अब बिना डरे काम कर रहे हैं।

ममता का विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका बहुत साफ है। वे हर घटना को अपने खिलाफ साजिश बताती हैं। रोना-धोना शुरू कर देती हैं। समर्थकों को उकसाती हैं। कहती हैं कि बंगाल की अस्मिता खतरे में है।

लेकिन इस बार यह चाल चल नहीं रही। जनता देख रही है कि अर्धसैनिक बल ने कैसे शांति लाई। 2021 के दंगों की यादें ताजा हैं। लोग हिंसा से त्रस्त थे। अब वे शांत चुनाव चाहते हैं। ममता का गुस्सा इसी से भड़कता है। वे जानती हैं कि सत्ता खिसक रही है। भाजपा का माहौल मजबूत हो गया है। कार्यकर्ता बिना डर के प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की यह चुनावी जंग लोकतंत्र की जीत बन रही है। अर्धसैनिक बल और चुनाव आयोग की सख्ती ने हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी का विक्टिम कार्ड फेल हो गया। उदाहरण गिनाने को तो बहुत हैं। हर जिले से ऐसी कहानियां आ रही हैं। जनता अब सच्चाई चुन रही है। यह बदलाव ऐतिहासिक है। बंगाल की धरती पर शांति का राज कायम हो रहा है।

श्यामपुर क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों से लोगों में रोष

हरिद्वार । श्यामपुर, कांगड़ी, गाजीवाली और सजनपुर पीली क्षेत्र की गलियों में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों के कारण रात के समय अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मुख्य गलियों और चौक-चौराहों पर लगी कई लाइटें बंद या क्षतिग्रस्त हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले विद्युत खंभों पर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं और बाद में विभिन्न योजनाओं के तहत सोलर लाइटें भी स्थापित की गईं, जिससे रात में आवाजाही सुगम हो गई थी। लेकिन समय के साथ रखरखाव के अभाव, तेज हवाओं और बंदरों की गतिविधियों के चलते अधिकांश लाइटें खराब हो गई हैं। स्थिति यह है कि कई जगहों पर केवल खंभे ही खड़े रह गए हैं, कहीं लाइटें गायब हैं तो कहीं सोलर पैनल तक नहीं बचे हैं। कुछ स्थानों पर आंशिक रोशनी जरूर है, लेकिन अधिकांश गलियां घने अंधेरे में डूबी रहती हैं। अंधेरे के कारण न केवल लोगों को रात में आने-जाने में परेशानी हो रही है, बल्कि सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई हैं।

क्रेजी टीम बनी बीएचईएल कैनवास प्रीमियर कप 2026 की चैंपियन

हरिद्वार । बीएचईएल हरिद्वार के खेल मैदान पर पिछले ढाई महीने से चल रहे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट 'बीएचईएल कैनवास प्रीमियर कप 2026' का बुधवार को समापन हो गया है। फाइनल मुकाबले में क्रेजी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पार्टन टीम को 22 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। एक फरवरी से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में नौ टीमों ने भाग लिया। राउंड रॉबिन और प्लेऑफ प्रारूप में खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। फाइनल मैच में क्रेजी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में आठ विकेट खोकर 161 रन बनाए। टीम की ओर से बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल दिखाते हुए मजबूत स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी स्पार्टन टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 14.5 ओवर में 139 रन पर सिमट गई। क्रेजी टीम की अनुशासित गेंदबाजी और शानदार क्षेत्ररक्षण के आगे स्पार्टन टीम टिक नहीं सकी। समापन समारोह में मुख्य अतिथि वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन विनीत कुमार ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन कर्मचारियों की शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के साथ आपसी समन्वय और खेल भावना को भी मजबूत करते हैं।

चारधाम में हरिद्वार की दस कंपनियों को बस संचालन में मिली जगह

हरिद्वार । आगामी चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित और यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में प्राइवेट बस संचालन करने वाली कंपनियों में इस बार हरिद्वार की कंपनी को भी शामिल किया गया है। अब नौ की जगह दस कंपनियां चारधाम यात्रियों को बस सेवा उपलब्ध कराएंगी। बुधवार को कनखल स्थित त्रिपुरा आश्रम में संयुक्त रोटेशन चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति के तत्वावधान में आयोजित बैठक में बसों के रोटेशन, गैस सिलेंडर की आपूर्ति और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बस संचालकों और विभिन्न ट्रैवल एजेंट कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यातायात सहकारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र नेगी ने बताया कि इस बार हरिद्वार लक्जरी बस एसोसिएशन को भी शामिल किया गया है, जिससे स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और यात्रियों को बेहतर व किफायती सेवा मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि सभी कंपनियों की सहमति से बसों का संचालन तय रोटेशन प्रणाली के तहत किया जाएगा, ताकि किसी भी यात्री को असुविधा न हो।

'चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के साथ करें शालीन व्यवहार'

हरिद्वार । आगामी चारधाम यात्रा सीजन को सुरक्षित, सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए हरिद्वार पुलिस ने टैक्सी यूनियनों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा, यातायात नियमों के पालन, निर्धारित किराया सूची प्रदर्शित करने और वाहनों में फर्स्ट-एड बॉक्स रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में कहा गया कि चारधाम यात्रा के दौरान देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ मधुर और शालीन व्यवहार किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंगलवार को ट्रैफिक कार्यालय हरिद्वार में पुलिस उपाधीक्षक यातायात विपेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें हरिद्वार क्षेत्र की सभी टैक्सी यूनियनों के प्रतिनिधि, वाहन स्वामी और चालक शामिल हुए। सभी वाहन स्वामी अपने वाहनों में निर्धारित किराया सूची अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें, ताकि यात्रियों से किसी प्रकार की अनियमित वसूली न हो। साथ ही फर्स्ट-एड बॉक्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। यात्रा सीजन के दौरान यात्री सुरक्षा, यातायात नियमों का पालन और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।

कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार में मखाना की खेती का किया औपचारिक शुभारंभ

हरिद्वार ।प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपद हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र स्थित गंगदासपुर बालावाली में मणिगाछी एफपीओ द्वारा शुरू किए गए मखाना की खेती के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं मखाना रोपण कर हरिद्वार जनपद में मखाना खेती की औपचारिक शुरुआत की। गौरतलब है कि बिहार की एक संस्था द्वारा उत्तराखण्ड में पहली बार हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में मखाना खेती का पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना का शुभारंभ कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा किया गया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने संस्था के पदाधिकारियों को इस प्रयास के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं भी दी।

इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन किया गया, जो उत्तराखण्ड सहित देश के 11 राज्यों में मखाना उद्योग को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक रुपये 476 करोड़ के परिव्यय के साथ मखाना विकास हेतु केंद्र पोषित योजना संचालित की जा रही है, जिसमें अनुसंधान, गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन, कौशल विकास, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, विपणन एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के अंतिम त्रैमास में उत्तराखण्ड को रुपये 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्र धनौरी (हरिद्वार), ढकरानी (देहरादून) एवं काशीपुर (उधमसिंहनगर) के सहयोग से किसानों को मखाना उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित किए जा रहे हैं, साथ ही प्रदर्शन प्लॉट भी स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए रुपये 143.16 लाख की कार्ययोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार उत्तराखण्ड को औद्यानिकी प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। सेब की अति सघन बागवानी के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में 230 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 क्लस्टर विकसित किए गए हैं। इसके अलावा मिलेट्स, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग नीतियां लागू की गई हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विश्वास व्यक्त किया कि इन सभी प्रयासों से प्रदेश के किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर उद्यान विभाग से बागवानी निदेशक महेन्द्र पाल, मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह, संस्था के अध्यक्ष राजीव रंजन, डॉ. प्रेम कुमार, अजय पैनोली, अनुज प्रधान, दीपक सैनी, अजय शर्मा, कृष्णपाल चौहान, बाबूराम सहित बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित रहे।

गुरुद्वारा ज्ञान गोदडी के लिए कूच कर रहे सिक्ख लोगों को पुलिस ने रोका

हरिद्वार । गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी मूल स्थान के लिए सिक्ख समाज ने श्री गुरु नानक देव धर्म प्रचार समिति के तत्वावधान में ग्राम दिनारपुर से हरकी पैड़ी तक कूच किया। बैसाखी पर सिक्ख संगत मूल स्थान पर अरदास और गंगा स्नान करने जा रही थी, लेकिन पुलिस ने डांडी चौक पर ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प और नोकझोंक भी हुई। इसके बाद संगत सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। लोगों ने कहा कि पिछले चार दशक से गुरुद्वारे के लिए समाज सड़क पर धरना-प्रदर्शन कर रहा है लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। हरकी पैड़ी के पास जिस स्थान पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी था उसे प्रशासन वापस नहीं कर रहा है। यह स्थान सिक्ख समाज के लिए बहुत पवित्र है, जिसे प्रशासन समाज को वापस करे। ऐसा नहीं करने से लोगों में बहुत रोष है। एक घंटा धरने के बाद कुंभ एसडीएम मंजीत सिंह ने संगत से वार्ता कर कुछ दिन का समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनकी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी और मुख्यमंत्री से इस प्रकरण पर एक प्रतिनिधिमंडल की वार्ता करवाई जाएगी। भाकियू (टिकैत) ने भी संगत को समर्थन दिया। इस अवसर पर समिति संरक्षक बाबा पंडत, अध्यक्ष सूबा सिंह ढिल्लों, सुखदेव सिंह, संजय चौधरी, विजयपाल सिंह, गुरचरण सिंह, लखविंदर कौर, सुरेंद्र कौर, प्रभजोत कौर, गुरनाम सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत कौर, नरेंद्र कौर, मनप्रीत कौर, सुखविंदर कौर, निर्मल कौर, सहजदीप कैर, हरज़ेब कौर, तनवीर सिंह आदि सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

रोजगार और पर्यटन का ग्रीन कॉरिडोर बनेगा दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर

देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली- देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का लोकार्पण कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के लिए रोजगार और पर्यटन का ग्रीन कॉरिडोर शुरू हो गया है। अब दिल्ली- देहरादून का सफ़र महज़ ढाई घंटे का में पूरा हो जाएगा इसके साथ ही चारधाम यात्रा, कॉर्बेट एवं राजाजी नेशनल पार्क, मसूरी, टिहरी और उत्तराखंड के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर आने वाले सैलानियों की बड़ी संख्या में तादात बढ़ने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर केवल एक परिवहन परियोजना नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला 'ग्रीन कॉरिडोर' साबित होने जा रहा है। यह कॉरिडोर पहाड़ और मैदान के बीच दूरी को कम करते हुए किसानों, उद्यमियों और स्थानीय उत्पादकों को सीधे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने का सशक्त माध्यम बनेगा। अब हर्षिल के प्रसिद्ध सेब, जोशीमठ और चकराता की राजमा, पुरोला के लाल चावल, तथा रुद्रप्रयाग के बुरांश का जूस जैसे पारंपरिक और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से और कम लागत पर बड़े शहरों तक पहुँच सकेंगे। लॉजिस्टिक लागत में कमी आने से किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिरता आएगी।

भारतीय शासन व्यवस्था की पटकथा फिर से लिख रहा है मिशन कर्मयोगी

डॉ जितेंद्र सिंह

कल्पना करें कि राजस्थान के दूरदराज के किसी कोने में जिला कलेक्टर को एक ऐसी महत्वाकांक्षी कल्याण योजना की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसके बारे में उसकी जानकारी बहुत कम है। एक दशक पहले उसे जानकारी के लिए कहीं धूल खा रही किसी नियमावली का सहारा लेना होता। या फिर वह अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी की तीन बैठकों और लंच के बाद खाली होने का इंतजार करता। उसकी उम्मीद उस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी टिकी हो सकती थी जो शायद एक या दो साल में कभी आता। लेकिन आज वह अपने फोन के जरिए आईगॉट (इंटिग्रेटेड गर्वनमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म) पर लॉग ऑन करता है। उसे मिनटों में ही अपनी जरूरत के अनुरूप एक सुव्यवस्थित कार्यकुशलता आधारित पाठ्यक्रम मिल जाता है। वह शाम तक सूचनाओं और आत्मविश्वास से लैस होकर योजना के लाभार्थियों की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहा होता है। यह बदलाव देखने में छोटा लग सकता है मगर हकीकत में किसी क्रांति से कम नहीं है।

चमक-दमक से दूर धैर्य के साथ पांच साल पहले शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी एक क्रांति ला रहा है। यह नए भारत के लिए एक नई तरह के प्रशासनिक अधिकारी तैयार करने के उद्देश्य से चुपचाप काम कर रहा है।

इसके महत्व को समझने के लिए हमें पहले संदर्भ को जानना होगा। 2047 तक विकसित भारत के प्रधानमंत्री के निर्धारित लक्ष्य तक यूं ही नहीं पहुंचा जा सकता। इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें भारत गणतंत्र को चलाने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों के जरिए सावधानी से एक-एक कदम आगे बढ़ना होगा। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण पूंजी, प्रौद्योगिकी या नीति नहीं है। सबसे ज्यादा अहमियत उन लगभग 3.5 करोड़ प्रशिक्षित, उत्साही और नागरिक केंद्रित सरकारी कर्मियों की क्षमता की है जो हर सुबह उठ कर भारतीय शासन को संचालित करते हैं।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में ज्यादातर समय क्षमता निर्माण का मॉडल सांयोगिक रहा है। किसी नौजवान अधिकारी को सेवा की शुरुआत के समय औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर करियर के बीच में यदा-कदा उसे कुछ पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर मिल सकता था। बाकी, उसे काम करते हुए और दूसरों को देख कर ही सीखना होता था। एक स्थिर और धीमी गति से आगे बढ़ते विश्व में यह काफी था। लेकिन कृत्रिम मेधा, जलवायु अवरोध, जनसांख्यिकीय दबाव और जबर्दस्त प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के युग में यह सरासर नाकाफी है। प्रशासन के सामने चुनौतियां जिस रफ्तार से आती हैं उसके सामने प्रशिक्षण की पुरानी प्रणालियों की गति कहीं नहीं टिकती।

मिशन कर्मयोगी को इसी बेमेल स्थिति के समाधान के रूप में की गई थी। 2021 में शुरू किया गया यह मिशन—जिसे उसी वर्ष अप्रैल में स्थापित क्षमता निर्माण आयोग द्वारा संस्थागत रूप से संचालित किया गया, एक सचमुच महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। भारतीय सिविल सेवाओं की सीखने की संस्कृति को, समय-समय पर होने वाली और केवल नियमों के पालन तक सीमित प्रक्रिया से बदलकर, एक निरंतर चलने वाली, भूमिका-आधारित और स्वयं-निर्देशित विकास यात्रा में रूपांतरित करना इसका मकसद है। जैसा कि आयोग इसका वर्णन करता है, यह बदलाव कर्मचारी—यानी नियमों का पालन करने वाले एक पदाधिकारी से कर्मयोगी बनने की ओर है: एक ऐसा लोक सेवक जो किसी उद्देश्य, सेवा-भाव और उत्कृष्टता से प्रेरित हो।

पाँच वर्षों के बाद, ये आंकड़े अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। 'आईगॉट' (इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग) प्लेटफॉर्म पर अब 1.5 करोड़ से अधिक सरकारी अधिकारी सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में जुड़े हैं — यह एक ऐसी संख्या है जो शुरुआत के समय काल्पनिक लगती थी। 4,600 से अधिक योग्यता-आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से, इन अधिकारियों ने 8.3 करोड़ से अधिक पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। अकेले पिछले राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के दौरान, भागीदारी के परिणामस्वरूप 4.5 मिलियन घंटे के पाठ्यक्रम नामांकन और 3.8 मिलियन घंटे की वास्तविक शिक्षा दर्ज की गई। ये केवल अमूर्त आंकड़े नहीं हैं। दर्ज किया गया प्रत्येक घंटा भारत में कहीं न कहीं एक लोक सेवक का प्रतिनिधित्व करता है — छत्तीसगढ़ में एक राजस्व निरीक्षक, पुणे में एक शहरी स्थानीय निकाय अधिकारी, मणिपुर में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये सब अपने साथी नागरिकों की बेहतर सेवा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहें हैं।

जो बात आईगॉट प्लेटफॉर्म को वास्तव में परिवर्तनकारी बनाती है, वह केवल इसका पैमाना नहीं है, बल्कि इसकी पहुँच की संरचना है। यह किसी भी समय और कहीं भी, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप पर, कई भाषाओं में उपलब्ध है, और इसे शिक्षार्थी के पेशेवर प्रोफाइल के अनुसार बनाया गया है। पाठ्यक्रमों को हर तीन से छह महीने में अपडेट किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शासन में एआई टूल का उपयोग कैसे करें या नए वित्तीय नियमों को कैसे समझें, इससे संबंधित सामग्री वर्तमान और प्रासंगिक बनी रहे। दूसरे शब्दों में, यह प्लेटफॉर्म धूल फांकने वाली कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है — बल्कि यह सीखने का एक जीवंत और अनुकूलन योग्य तंत्र है। इस पर विचार कीजिए कि एक आदिवासी जिले की जूनियर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए इसका क्या अर्थ है, जिसे उसकी अपनी भाषा में बाल पोषण मूल्यांकन के नवीनतम प्रोटोकॉल समझाने वाला एक मॉड्यूल प्राप्त होता है। उसे अपने ब्लॉक में किसी प्रशिक्षक के आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वह सीखती है, और कार्य करती है। यही इस मिशन का लोकतांत्रिक लाभांश है।

क्षमता निर्माण आयोग, इस तंत्र के रणनीतिक संरक्षक के रूप में, एक साथ वास्तुकार और संचालक दोनों की भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय नीति बनाने वाले एक सचिव से लेकर ग्राम स्तर पर इसे लागू करने वाले एक पंचायत पदाधिकारी तक, यह पहचान करता है कि सार्वजनिक भूमिकाओं के विशाल स्पेक्ट्रम में किन योग्यताओं की आवश्यकता है। यह सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 ढांचे के माध्यम से देश के प्रशिक्षण संस्थानों के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करता है, जिसके तहत देश भर के 200 से अधिक प्रशिक्षण संस्थान पहले ही मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। यह राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। सभी 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब औपचारिक समझौता ज्ञापनों के माध्यम से जुड़ चुके हैं ताकि ऐसी विशिष्ट क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार की जा सकें जो कार्यबल की दक्षताओं को संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ जोड़ती हैं। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम जैसी ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से, इसने एक मिलियन से अधिक प्रमाणित अधिकारियों को बड़े पैमाने पर व्यवहार प्रशिक्षण दिया है, जो प्रत्येक नागरिक को अंतिम हितधारक के रूप में मानने की सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण कला है।

मिशन के इस अंतिम आयाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ के बारे में है जिसे पूर्णता प्रमाण पत्र या लॉग किए गए घंटों में आसानी से नहीं मापा जा सकता। मिशन कर्मयोगी की सबसे गहरी आकांक्षाओं में से एक है—दृष्टिकोण में बदलाव। यह राज्य और नागरिक के बीच एक लेन-देन वाले संबंध से हटकर नागरिक देवो भव की भावना से परिभाषित संबंध की ओर एक आंदोलन है: नागरिक ईश्वर के समान है, वह सर्वोच्च अधिकारी है जिसके प्रति राज्य का सेवक जवाबदेह है। जब रेलवे काउंटरों, राजस्व कार्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों पर नागरिक-केंद्रित अधिकारियों को इसके तहत प्रशिक्षित किया गया और बाद में नागरिकों का सर्वेक्षण किया गया तो प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। उन्होंने बदलाव को महसूस किया। न केवल दक्षता में, बल्कि व्यवहार की आत्मीयता, तत्परता और बातचीत की मानवीय गुणवत्ता में भी। एक ऐसे युग में जब एआई प्रशासनिक कार्यों के विशाल हिस्सों को स्वचालित करने की चुनौती दे रहा है, यह मानवीय परत, जो सहानुभूतिपूर्ण, सांस्कृतिक रूप से जागरूक और स्थानीय जड़ों से जुड़ी है कोई फालतू चीज़ नहीं, बल्कि भारत के शासन की सर्वोच्च शक्ति है।

इस मिशन ने अपनी तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के साथ-साथ भारत की बौद्धिक विरासत का सम्मान करने का भी एक सचेत प्रयास किया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रकोष्ठ के माध्यम से, पारंपरिक ज्ञान जिसमें सामुदायिक शासन और कृषि से लेकर वित्त और स्वास्थ्य सेवा तक के क्षेत्र शामिल हैं — को प्रशिक्षण सामग्री के ताने-बाने में बुना जा रहा है; इसे केवल अतीत की यादों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। अमृत ज्ञान कोष भंडार, जिसमें 70 से अधिक पूर्ण केस स्टडीज़ शामिल हैं, शासन-प्रशासन से जुड़े ऐसे ज्ञान का एक संग्रह तैयार कर रहा है जिसकी जड़ें भारतीय संदर्भों और भारतीय समाधानों में निहित हैं। प्रशासनिक मानसिकता का यह वि-औपनिवेशीकरण, जिसके तहत भारतीय लोक सेवकों को आधुनिक चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी ही सभ्यतागत विरासत के साथ आत्मविश्वासपूर्ण जुड़ाव स्थापित करने की ओर लौटाया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख आकांक्षाओं में से एक है और मिशन कर्मयोगी इसी आकांक्षा को साकार रूप दे रहा है।

साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल तक मनाया जाने वाला राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह — इस पांच वर्षीय यात्रा का उत्सव और इसके अधूरे कार्यों के प्रति पुनर्संकल्प, दोनों है। साधना शब्द यहाँ अत्यंत उपयुक्त है। इसका अर्थ है समर्पित अभ्यास; एक ऐसे व्यक्ति का अनुशासित दैनिक प्रयास जो किसी एक असाधारण कार्य के माध्यम से नहीं, बल्कि अपने कौशल के प्रति निरंतर समर्पण के माध्यम से निपुणता प्राप्त करना चाहता है। जैसे ही हम सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ इस सप्ताह का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें लगभग 700 वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और 3,000 से अधिक वर्चुअल माध्यम से शामिल हो रहे हैं, हम केवल एक वर्षगाँठ नहीं मना रहे हैं। हम अगले पांच वर्षों के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं — एक ऐसे भविष्य की ओर जिसमें हर स्तर पर प्रत्येक सिविल सेवक निरंतर सीखने वाला, एक नागरिक-चैंपियन और भारत की आकांक्षाओं का एक आत्मविश्वासी संरक्षक होगा।

विकसित भारत 2047 के लक्ष्य — सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से लेकर शून्य शुद्ध उत्सर्जन के संकल्प तक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से लेकर वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व तक, केवल नीतिगत माध्यम से पूरे नहीं होंगे। वे लोगों के माध्यम से पूरे होंगे: उस जिला अधिकारी द्वारा जो योजना को सही ढंग से समझ कर उसे पूरी शुद्धता के साथ लागू कर सके; उस शहरी योजनाकार द्वारा जो स्थानिक डेटा टूल का उपयोग कर सके; उस अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट को इस तरह संप्रेषित करे कि उसका समुदाय उस पर भरोसा करे। मिशन कर्मयोगी न केवल कल के लिए, बल्कि आने वाले दशकों के लिए उसी दल का निर्माण कर रहा है।

भारत की शासन-व्यवस्था की कहानी के लंबे और प्रकाशमान सफर में, यह शायद वह अध्याय है जिसमें शासन ने आखिरकार सीखना सीख लिया।

(लेखक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री हैं)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिमी बंगाल अग्नि परीक्षा?

अजय दीक्षित

23 और 29 अप्रैल को होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष महत्व रखते हैं इन चुनावों की उतनी ही अहमियत है जितनी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की होती है बल्कि उससे इस मायने में अधिक है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में अटलविहारी वाजपई के समय से जनाधार जुटाने में लगी है। अटलजी के मंत्री परिषद में तपन सिकदर पहली बार राज्य मंत्री 1999 में बने थे ।तब से भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है ।2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 04 सीट मिली थी लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 03 सीट मिली पर वोट शेयर 10 फीसदी था ।तब पश्चिमी बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान पर थी । तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बैठी और ममता बनर्जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उस के बाद पश्चिमी बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लिया और 2019 लोकसभा चुनाव में

भाजपा को 39 फीसदी वोट और 42 में से 18 सीट मिली थी सीपीएम,कांग्रेस का एक एक सांसद चुना गया था यही से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल यात्रा शुरू हुई ।सीपीएम का वोट शेयर मात्र 8 फीसदी पर आ गया और कांग्रेस का 03 फीसदी ।2024 के लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में 77 विधायक जीतकर आए ।वोट शेयर 39 फीसदी मिला । उल्लेखनीय यह रहा कि नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इन चुनावों में ममता बनर्जी ने बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठाया और वह कामयाब रहा था लेकिन इस बार भाजपा ने रणनीत बदलकर ममता बनर्जी की सरकार को केंद्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव की अपने हाथ में ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, मुर्शिदाबाद की रैली में राज्य के विकास, महिलाओं की स्थिति, सरकार का भ्रष्टाचार, तृणमूल कांग्रेस की मनमानी,को मुख्य रूप से उठाया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखता है। पश्चिमी बंगाल से 2029 लोकसभा चुनाव का रास्ता निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता कि 2029 में भाजपा अकेले दम पर 350 सीट जीते उसके लिए पश्चिमी बंगाल में 42 लोकसभा सीट पर भी उनकी नजर है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ, और विद्या भारती,बनवासी कल्याण परिषद,सेवा भारती, संस्कृत भारती,आदि बुनियादी संगठनों का फैलाव भी इस विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। पश्चिमी बंगाल में अवैध मुस्लिम, बांग्लादेशी घुसपैठ,सीमांत प्रदेश होने के कारण सामरिक विषय भी मुख्य मुद्दा है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 43 से 45 तक वोट शेयर करती है तो उसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक तबका चाहता है कि तुड़मूल के हिंदू समर्थक अगर जरा भी चेते तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एस आई आर को मुख्य मुद्दा बनाया है। लेकिन इस मुद्दे हवा निकल रही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार न्यायाधीश को काम पर लगाया है ।मालदा में कुछ मुस्लिम ने उन पर ही हमला कर दिया है ।अबकी बार चुनाव आयोग भी विशेष तैयारी से चुनाव कराने जा रहा है ।उसने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसकी देखभाल अनुविभागीय अधिकारी करेगा ।दो चरणों होने वाले चुनाव में बेहिसाब अर्धसैनिक बलों की तैनादगी की गई है।

फिल्म निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने की मुख्यमंत्री धामी से शिष्टाचार भेंट

उत्तराखंड को देश का अग्रणी फिल्म शूटिंग हब बनाने का संकल्प

देहरादून (संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज मुख्यमंत्री आवास में प्रख्यात फिल्म निर्माता-निर्देशक मधुर भंडारकर ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में एक अग्रणी गंतव्य के रूप में विकसित करने, निवेश को आकर्षित करने तथा राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, विविध भौगोलिक परिस्थितियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं शांत वातावरण के कारण फिल्म निर्माण के लिए अत्यंत उपयुक्त राज्य है। राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश-विदेश के फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बनाया जाए और इसे एक सशक्त फिल्म शूटिंग हब के रूप में स्थापित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई आधुनिक एवं उद्योगोन्मुख फिल्म नीति के अंतर्गत फिल्म निर्माताओं को आकर्षक सब्सिडी, टैक्स छूट तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से शूटिंग से संबंधित सभी अनुमतियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे फिल्म निर्माण प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम बनाया जा सका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब तक व्यापक स्तर पर कार्य किए गए हैं। राज्य में अनेक हिंदी फिल्मों, क्षेत्रीय फिल्मों, टीवी धारावाहिकों एवं वेब सीरीज़ की शूटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई है, जिससे उत्तराखंड देश के प्रमुख फिल्म निर्माण स्थलों में तेजी से उभरकर सामने आया है। यहां की वादियां, झीलें, धार्मिक स्थल एवं ऐतिहासिक लोकेशन फिल्म निर्माताओं को विशेष रूप से आकर्षित कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तराखंड को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 'मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट' का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, जो राज्य सरकार की नीतियों और व्यवस्थाओं की सफलता का प्रमाण है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फिल्म शूटिंग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोकेशन बैंक तैयार किया गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र, झीलें, वन क्षेत्र, ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक धाम शामिल हैं। इससे फिल्म निर्माताओं को विविध और आकर्षक लोकेशन एक ही मंच पर उपलब्ध हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिल्म उद्योग के माध्यम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों एवं युवाओं को फिल्म निर्माण प्रक्रिया से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही फिल्म एवं मीडिया से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म सिटी के विकास की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे फिल्म निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को राज्य के भीतर ही संचालित किया जा सके। इसके साथ ही फिल्म महोत्सवों एवं सांस्कृतिक आयोजनों को प्रोत्साहित कर राज्य की पहचान राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त बनाई जा रही है। इस अवसर पर मधुर भंडारकर ने उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता एवं अनुकूल वातावरण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग करने की इच्छा भी व्यक्त की। मुख्यमंत्री धामी ने विश्वास व्यक्त किया कि फिल्म उद्योग के क्षेत्र में किए जा रहे ये प्रयास न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार फिल्म निर्माताओं को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है।

'युवा जागा तो बदलेगा देश-आंबेडकर जयंती पर देहरादून से कन्हैया ने दिया बड़ा संदेश'

देहरादून (संवाददाता)। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के अवसर पर देहरादून में 'जय भीम, जय हिंद' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संचार सचिव वैभव वालिया द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने किया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में छात्र संगठन हस्ढ्ढ के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार उपस्थित रहे। अपने तीखे और प्रभावशाली संबोधन में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान देश की आत्मा है, लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग उसी संविधान की मूल भावना पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा सत्ताधारियों के द्वारा नारा तो देश का दिया जा रहा है लेकिन खजाना दोस्त का भरा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में नफरत, असमानता और अन्याय को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बाबा साहेब के सपनों के भारत के बिल्कुल विपरीत है।

उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि देश का युवा चुप न बैठे, बल्कि बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलते हुए अन्याय के खिलाफ खुलकर आवाज उठाए। 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का मंत्र आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक है। इस अवसर पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रही है, जबकि सरकारें केवल ध्यान भटकाने की राजनीति में लगी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों से लेकर सदन तक संघर्ष करती रहेगी।

नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज देश में सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांतों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर ही देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है, लेकिन आज उन अधिकारों को सीमित करने की साजिश हो रही है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक न्याय पहुंचाना ही बाबा साहेब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, और कांग्रेस पार्टी इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के अंत में आयोजक वैभव वालिया ने कन्हैया कुमार का, प्रदेश नेतृत्व का और सम्मेलन में आई हुई देव तुल्य जनता का धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया।

कार्यक्रम में विधायक रवि बहादुर ,युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह भोजक, उत्तराखंड हस्ढ्ढ के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, पूर्व काबिना मंत्री शूरवीर सिंह सजवान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप,अनिल नेगी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मदनलाल, महानगर अध्यक्ष डॉ जसविंदर गोगी, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी, अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष सुलेमान अंसारी, पूर्व विधायक राजकुमार,गौतम नौटियाल, नानक चंद पीयूष गॉड आयुष सेमवाल हेमंत उप्रेती ललित भद्री अजय रावत अमन सिंह अमन प्रजापति आलोक मेहता शहजाद अंसारी राव नसीम सी पी सिंह मोहन काला संजय कनौजिया उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं और आमजन ने भाग लिया और बाबा साहेब के आदर्शों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का संकल्प लिया। अंत में 'जय भीम, जय संविधान, जय हिंद' के गगनभेदी नारों के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की मसूरी में लगे प्रतिमा: जुगरान

मसूरी (संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र जुगरान ने मसूरी गोलीकांड में शहीद हुए तत्कालीन डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी की शहादत को शहीद का दर्जा भारत सरकार गृह मंत्रालय ने 32 वर्ष पहले ही उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इसका पता न तो उत्तराखंड की जनता को, न ही प्रदेश सरकार को न ही पुलिस मुख्यालय को न ही प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय को न ही उमाकांत त्रिपाठी के परिवार को इसका पता था और मसूरी राज्य आंदोलनकारी मंच सहित प्रदेश के आंदोलनकारी लंबे समय से उनको शहीद का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी लगातार इस संबंध में मिलते रहे। गत आठ मह पहले ही में धामी से फिर मिले व उन्होंने गृह मंत्रालय उत्तराखंड को लिखा उन्होंने पुलिस मुख्यालय को लिखा व लगातार उनसे संपर्क करत रहे, व तीन दिन पहले जब पुलिस मुख्यालय में आईजी कार्मिक डा. योगेंद्र सिंह रावत से मिले व उन्हांने लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से पत्राचार किया व उन्हांने वहां पुलिस के डाकिया को भेजा व तीन दिन पहले उन्हें ऑन रिकार्ड सूचना मिली कि उन्हें 1995 में शहीद का दर्जा मिल चुका है व दिल्ली में चाणक्यपुरी में जो शहीद स्तंभ है उसमें उनका नाम शहीदों में अंकित है। इसके बाद उन्होंने उमाकांत त्रिपाठी की पत्नी यशोधा त्रिपाठी से मिले व उन्हें यह सूचना दी, इसकी उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। उनकी मांग पहले ही पूरी हो चुकी थी लेकिन देर से जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार से मसूरी के आंदोलनकारी मिलें व उनके परिवार का अभिनंदन व सम्मान करे। प्रदेश सरकार उनकी भव्य प्रतिमा मसूरी शहीद स्थल पर लगाये व प्रदेश सरकार शहीद को जो अनुमन्य सुविधाएं होती है उनके परिवार को दी जाय। भले ही इसकी जानकारी 32 साल बाद मिली उससे आंदोलनकारियों में खुशी है। इस मौके पर वरिष्ठ आंदोलनकारी जय प्रकाश उत्तराखंडी ने कहा कि शहीद डीएसपी उमाकांत त्रिपाठी मृदुभाषी व ईमानदार अधिकारी थे व आंदोलनकारियों के साथ उनका अच्छा व्यवहार था। उनको दो सिंतबर मसूरी गोली कांड में गोली लगी व वे शहीद हो गये। उनको शहीद का दर्जा देने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास 2004 में गये जिन्होंने उनके कागज को फेंक दिया। उन्हांने कहा कि मसूरी के आंदोलनकारी उनके परिवार से मिलेंगे, उन्हे सम्मान दिया जायेगा व सरकार से उनकी मसूरी में प्रतिमा लगाने व उनके नाम पर सड़क का नाम रखने के साथ उनके परिवार को शहीद का सम्मान व सुविधाए देने की मांग की वहीं सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि उनको 32साल से शहीद का दर्जा मिलने के बाद भी उन्हें शहीद नहीं माना गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलकारी मंच के अध्यक्ष देवी गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आंदोलनकारियों के साथ उचित बर्ताव नहीं करती, यह भी उसी कड़ी का हिस्सा है कि उनको शहीद का दर्जा मिलने पर भी सरकार को पता नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जो भी राज्य आंदोलनकारी है चाहे वह सरकार व विपक्ष में विधायक है या रहे हैं उन्हें भी राजनीति से हटकर उमाकांत त्रिपाठी के सम्मान के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं मांग की मसूरी राज्य आंदोलन में पुलिस की बर्बरता सहने वालों व शहीदों के नाम पर किसी न किसी संस्थान, का नाम रखा जाना चाहिए उनके नाम के द्वार बनाया जाना चाहिए।

बड़ी अभिनेत्रियों को पीछे छोड़ वामिका गब्बी बनीं मेकर्स की पहली पसंद

अक्षय कुमार के साथ भूत-बंगला से सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली वामिका गब्बी के लिए साल 2026 बेहतरीन होने वाला है क्योंकि अभिनेत्री सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही नहीं, बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा में भी धूम मचाने के लिए तैयार हैं। अभिनेत्री की एक नहीं, बल्कि 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर इस साल दस्तक दे सकती हैं, जो कॉमेडी से लेकर एक्शन के जॉनर में होने वाली हैं। इन सभी फिल्मों में अभिनेत्रियों का अलग-अलग अवतार फैंस को देखने को मिलने वाला है।

वामिका भूत-बंगला के साथ 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देंगी। फिल्म हॉरर और कॉमेडी का मिक्स कॉकटेल होने वाली है। फिल्म को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि दर्शक डरने के साथ पेट पकड़कर हंसने भी वाले हैं। वामिका 4 साल बाद मलयालम सिनेमा में वापसी के लिए तैयार हैं। वह टिकी टाका फिल्म में अभिनेत्री आसिफ अली के साथ लीड रोल में दिखने वाली हैं। फिल्म पहली 2025 में दिसंबर के महीने में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब फिल्म मई के महीने में रिलीज हो सकती है। फिल्म का निर्देशन रोहित वीएस कर रहे हैं, जो पहले से ही अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

सिर्फ मलयालम में ही नहीं, वामिका तमिल सिनेमा में फेंटसी फिल्म जिनी में महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाली है। फिल्म का निर्देशन अर्जुनन जूनियर कर रहे हैं और फिल्म में वामिका के अलावा, जयम रवि और कल्याणी प्रियदर्शन भी लीड रोल में हैं। अभी तक फिल्म का पोस्टर सामने आया है जिसमें सभी लोग काल्पनिक किरदारों में दिख रहे हैं। फिल्म इसी साल, 2026, में रिलीज होगी। इसके अलावा वामिका दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग और पति पत्नी और वो दो में दिखने वाली हैं। दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग रोमांटिक और कॉमेडी का मिक्स कॉकटेल है, जबकि पति पत्नी और वो दो में जबरदस्त कॉमेडी और रिश्तों की नोक-झोंक दिखने वाली है। दोनों ही फिल्में इसी साल पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं। दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग की शूटिंग भी लगभग पूरी हो चुकी है। वामिका किकली के जरिए पंजाबी सिनेमा में भी एक्शन करती नजर आने वाली है। किकली आगामी एक्शन-थ्रिलर फिल्म में मंदी तखर और जोबनप्रीत लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि फिल्म इस साल के आखिर तक रिलीज हो जाएगी। वहीं, अभिनेत्री एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्म जी-2 में भी दिखने वाली है। कहा जाता रहा है कि फिल्म मई के आखिर में रिलीज हो सकती है।

आधी पिनिसेट्टी और लक्ष्मी मेनन की हॉरर-थ्रिलर शब्दम्, ओटीटी पर कर रही ट्रेंड, सस्पेंस-डर का है कॉम्बो, कहानी देख छूटने लगेंगे पसीने

ओटीटी पर देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपको सिर्फ डरावनी कहानी देखना पसंद है तो हम आपको साल 2025 में रिलीज हुई एक ऐसी हॉरर-थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने 2026 में ओटीटी पर दस्तक दी। ऐसे में अगर आपको भी हॉरर जॉनर की फिल्में और सीरीज देखना पसंद है, जिसे देख रातों की नींद उड़ जाए, हर सीन को देख डर लगे और किसी की आहट से मन परेशान हो जाए। अरिवझगन द्वारा निर्देशित इस तमिल हॉरर-थ्रिलर फिल्म में आधी पिनिसेट्टी और लक्ष्मी मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसकी कहानी, कास्ट और सीन देख आपको मजा आ जाएगा।

इस हॉरर-थ्रिलर फिल्म का नाम है शब्दम् है, जो फरवरी 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। सिनेमाघरों में रिलीज होने के एक साल से भी ज्यादा समय के बाद यह फिल्म अब ओटीटी पर उपलब्ध है। शब्दम् ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रही है और यह 24 मार्च, 2026 को ओटीटी पर रिलीज हुई है। इसकी डिजिटल रिलीज के बारे में आधिकारिक जानकारी प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर की थी। शब्दम् एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की कहानी है, जो मुन्नार के एक मेडिकल कॉलेज में हुई रहस्यमयी मौतों की एक कड़ी के पीछे छिपी एक भयानक अलौकिक शक्ति का पता लगाता है। वह डॉ. अवंतिका के साथ मिलकर 40 साल पुराने एक रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, जिसमें बच्चों पर किए गए दुखद प्रयोग शामिल हैं। जैसे-जैसे वह इन मौतों के बीच के संबंध का पता लगाने की कोशिश करता है, उसे एहसास होता है कि उसकी अब तक की खोज तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा भर है और इन सबके पीछे एक दुष्ट आत्मा छिपी हुई है। आखिर में वह इन्वेस्टिगेटर किस तरह सच्चाई का पता लगाता है, यही इस फिल्म में दिखाया गया है।

शब्दम् में मुख्य भूमिका में आधी पिनिसेट्टी हैं और उनके साथ लक्ष्मी मेनन, सिमरन, लैला, आरती अश्विन, रेडिन किंग्सले, एम.एस. भास्कर, राजीव मेनन, विवेक प्रसन्ना और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। तमिल रॉकर्स वेब सीरीज से मशहूर हुए अरिवझगन द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म को 7जी फिल्म्स और अल्फा फ्रेम्स के बैनर तले शिवा और एस भानुप्रिया शिवा ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बता दें कि इसे आईएमडीबी पर 6.1 रेटिंग मिली है।

'धुरंधर 2' ने दुनियाभर में काट दिया गदर, कलेक्शन हुआ 1000 करोड़ के पार, पठान, आरआरआर, केजीएफ 2 समेत इन फिल्मों को पछाड़ा

धुरंधर 2 ने अपनी रिलीज का एक हफ्ता पूरा कर लिया है. धुरंधर 2 बीती 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म का पेड प्रीव्यू शो भी चला था. फिल्म ने पेड प्रीव्यू और ओपनिंग डे पर मिलकर 145 करोड़ रुपये कमाए थे. अब सात दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपये के पार जा चुका है. दूसरी तरफ भारत में धुरंधर 2 ने 600 करोड़ रुपये से ज्यादा कमा लिए हैं. फिल्म धुरंधर 2 ने सातवें दिन की कमाई से भी कई फिल्मों के रिकॉर्ड मिट्टी में मिला दिए हैं. चलिए जानते हैं धुरंधर 2 ने सातवें दिन कितनी कमाई की है और क्या-क्या रिकॉर्ड तोड़े और बनाए हैं.

धुरंधर 2 ने सात दिनों में वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये कमाकर दूसरी सबसे तेज 1000 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म का खिताब अपने नाम कर लिया है. अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा 2 ने 6 दिनों में सबसे तेज वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. प्रभास की बाहुबली 2 ने 9 दिनों में 1000 करोड़ रुपये कमाए थे. इस लिस्ट में धुरंधर 2 ने बाहुबली 2 के साथ-साथ आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2, कल्कि 2898 एडी और पठान, जवान को भी पीछे छोड़ दिया है. अब अपने आठवें दिन की कमाई से धुरंधर 2 शाहरुख की पठान और प्रभास की कल्कि 2898 एडी के लाइफटाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन (1050 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है.

वहीं, बात करें फिल्म के सातवें दिन के कलेक्शन की तो बता दें, फिल्म की कमाई में 16 फीसदी की गिरावट महसूस हुई और फिल्म ने 47.70 करोड़ रुपये की कमाई की. इसी के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 623 करोड़ रुपये हो गया है. कहा जा रहा है कि इस वीकेंड फिल्म भारत में 800 करोड़ रुपये आसानी से कमा लेगी. साथ ही वर्ल्डवाइड धुरंधर के लाइफटाइम कलेक्शन 1300 करोड़ रुपये का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है. विदेशों में धुरंधर 2 अभ तक 261 करोड़ रुपये का कारोबार कर चुकी है. वर्ल्डवाइड फिल्म का कलेक्शन 1006 करोड़ रुपये हो गया है.

चॉकलेटी गाउन में कियारा आडवानी ने फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

कियारा आडवाणी ने हाल ही में मुंबई के एक अवॉर्ड फंक्शन में अपनी शानदार मौजूदगी से सबका ध्यान खींच लिया. उनका लुक इतना ग्लैमरस और क्लासी था कि फैंस उन्हें देखते ही रह गए. मां बनने के बाद उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और कॉन्फिडेंस नजर आया, जो उन्हें और खास बना रहा था. इसी बीच आइए कियारा की तस्वीरों और उनके लुक को देखते हैं.

कियारा ने अपने बालों को खुला रखा और हल्के वेव्स में स्टाइल किया. बालों का सॉफ्ट और नेचुरल लुक उनके चेहरे को बहुत खूबसूरती से फ्रेम कर रहा है. कियारा ने ब्राउन शेड की बॉडी-हगिंग ड्रेस पहनी है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है. ड्रेस का डिजाइन सिंपल होते हुए भी काफी स्टाइलिश था.

उनका मेकअप बहुत सटल और एलिगेंट है. ग्लोइंग स्किन, स्मोकी आईज और न्यूड लिप्स ने उनके चेहरे की नैचुरल ब्यूटी को और निखार दिया.

ड्रेस की डीप नेकलाइन और स्लीक डिजाइन ने उनके लुक को बोल्ड और अट्रैक्टिव बना दिया, जिससे लोगों की नजरें उनसे हट ही नहीं पा रही थी.

कियारा ने अपने लुक को मिनिमल रखते हुए सिर्फ एक स्टाइलिश चोकर नेकलेस पहना. यह ज्वेलरी उनके आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लग रही थी. उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल थी. कैमरे के सामने उनके हर पोज में एक अलग ही चार्म दिख रहा था, जो उनकी पर्सनालिटी को और खास बना रहा था. कियारा के लुक और उनकी प्रेजेंस ने इस शाम को खास बना दिया. सोशल मीडिया पर आई तस्वीरें अब फैंस के बीच वायरल हो गई है और हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

मीठे में कुछ नया खाना है तो ट्राई करें ये पांच यूनिक चॉकलेट रेसिपी

जब भी बात चॉकलेट की आती है तो लोगों के मन में चॉकलेट केक, चॉकलेट मूस, चॉकलेट केक जैसे डेजर्ट्स का ही ख्याल आता है लेकिन इससे कई तरह की यूनिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चों से लेकर बड़ो तक को चॉकलेट से बने तरह-तरह के व्यंजन खाना पसंद है तो इन पांच यूनिक रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इन व्यंजनों को घर पर बनाना कुछ ही मिनटों का काम है।

चॉकलेट पॉपकॉर्न

सबसे पहले एक पैन में लगभग चार बड़ी चम्मच मक्खन और आधा कप कॉर्न डालें। अब इसे ढक्कन को ढक दें और इन्हें फूटने दें। एक बार जब सारे कॉर्न पॉप हो जाएं तो इसमें लगभग तीन चौथाई कप कद्दूकस की हुई मिल्क चॉकलेट डालें। जब चॉकलेट अच्छे से पॉपकॉर्न में मिल जाएं तो इसे ढक दें। इसके बाद गरमागरम टॉकलेट पॉपकॉर्न को परोसें।

चॉकलेट समोसा

सबसे पहले एक बर्तन में मैदा, घी, बड़ी इलाइची के दाने और पानी को मिलाकर आटा गूंथ लें। इसके बाद चॉकलेट पिघलाएं और उसमें अपने पसंदीदा नट्स भूनकर मिलाएं। फिर आटे को छोटी-छोटी लोइयों में बांट लें और बेलन से प्रत्येक को चपटा कर लें। अब इन्हें काटकर कोन शेप देकर इनमें चॉकलेट मिश्रण भरें और इनके किनारों बंद कर दें। फिर इन्हें डीप फ्राई करने के बाद परोसें।

चॉकलेट रिसोट्टो

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा मक्खन गरम करें, फिर उसमें रिसोट्टो राइस डालें और दो मिनट तक भूनें। इसके बाद इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पकाएं। फिर इसमें थोड़ा वनिला एसेंस डालें और जब चावल पक जाएं तो इसमें दूध मिलाएं। अब इसमें थोड़ी चीनी और डार्क चॉकलेट मिलाएं। अंत में इसमें क्रीम और संतरे का छिलका मिलाकर इसे एक मिनट तक पकाएं। फिर इसे गरमागरम परोसें।

चॉकलेट पुडिंग

इसके लिए पहले एक कटोरे में चीनी, कोकोआ पाउडर, कॉर्नस्टार्च और एक चुटकी नमक को डालकर मिलाएं, फिर मिश्रण में दूध डालकर फेंटें। अब इस मिश्रण को गरम करें और मध्यम आंच पर धीरे-धीरे हिलाते हुए उबालें और दो मिनट तक मिश्रण को गाढ़ा होने तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण में वनिला एसेंस और मक्खन मिलाएं, फिर इस मिश्रण को छह घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद खाएं।

चॉकलेट फ्राइज

सबसे पहले फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज को सुनहरा होने तक डीप फ्राई करें। अब एक पैन में थोड़ा शहद गरम करें और इसमें फ्राइज को डालकर अच्छे से टॉस करें। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे एक कटोरे में निकाल लें और फ्राइज पर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इन यूनिक फ्राइज का सेवन करें।

बालों से हेयरस्प्रे हटाने के लिए अपनाएं ये आसान तरीके

हेयरस्प्रे का इस्तेमाल बालों की स्टाइलिंग के दौरान किया जाता है ताकि यह बिगड़े नहीं। लेकिन बाद में अपने बालों से हेयरस्प्रे हटाना ना भूलें क्योंकि यह स्कैल्प के रोमछिद्रों में घुसकर खुजली और बालों के झड़ने जैसी कई समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए हेयरस्प्रे को बालों से हटाना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं जिन्हें अपनाने से आपके लिए यह काम आसान हो सकता है।

डिश सोप का करें इस्तेमाल

अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपको यह जरूर पता होगा कि हेयरस्प्रे लगाने के बाद आपस में काफी उलझ जाते हैं और ऐसा हेयरस्प्रे के बिल्डअप से होता है। इसे हटाने के लिए आप डिश सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह आसानी से हेयरस्प्रे बिल्डअप को हटा सकते हैं। माइल्ड डिश सोप को अपने बालों पर लगाकर कंघी से फैलाएं। इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर बालों को धो लें।

बेकिंग सोडा आएगा काम

अकेले आपका नियमित शैंपू हेयरस्प्रे बिल्डअप को नहीं हटा सकता है इसलिए इसमें एक बड़ी चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाकर अच्छे से फैलाएं और इसे धोने से पहले थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आप बेकिंग सोडा को सीधे गीले बालों और स्कैल्प पर भी लगा सकते हैं। फिर इसे शैंपू से धो भी सकते हैं।

क्लैरिफाइंग शैंपू है प्रभावी

अगर आपको हर दिन हेयरस्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ता है तो इसके बिल्डअप को हटाने के लिए एक क्लैरिफाइंग शैंपू सबसे अच्छा है। क्लैरिफाइंग शैंपू में उच्च मात्रा में एसएलएस (डिटर्जेंट) होता है जो आपके स्कैल्प से किसी भी तरह के बिल्डअप और गंदगी को आसानी से हटा सकता है। हालांकि इसे हर दिन इस्तेमाल करने से बचें।

सेब का सिरका भी है कारगर

अगर सीमित मात्रा में सेब के सिरके का इस्तेमाल किया जाए तो यह न सिर्फ बालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है बल्कि किसी भी उत्पाद के बिल्डअप को आसानी से हटाने में भी कारगर साबित हो सकता है। लाभ के लिए एक कप पानी में एक बड़ी चम्मच सेब का सिरका मिलाएं। फिर इससे अपने बालों को गीला करें और थोड़ी देर बाद सिर को सामान्य शैंपू से साफ कर लें।

क्या उंगलियां चटकाना सेहत के लिए हानिकारक है? जानिए इस बात की सच्चाई

कई लोग तनाव में होने पर या खाली बैठे-बैठे अपनी उंगलियां चिटकाते रहते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत का सेहत पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है? यह एक आम धारणा है कि उंगलियां चटकाने से गठिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इस लेख में हम इसी भ्रम की सच्चाई जानेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई उंगलियों को चटकाने से कोई खतरा होता है या यह सिर्फ एक मिथक है।

लोग क्यों चिटकाते हैं उंगलियां?

उंगलियों को चटकाने का कारण अक्सर हवा के बुलबुले बनना होता है। जब आप उंगलियों को चिटकाते हैं तो आपके जोड़ों में दबाव बढ़ जाता है, जिससे हवा के बुलबुले बनते हैं और आवाज आती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सामान्य है और इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो आपके जोड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।

वैज्ञानिक नजरिए से इसे समझें

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि उंगलियों को चटकाने की आदत गठिया जैसी बीमारियों का कारण नहीं बनती। कई अध्ययनों में यह पाया गया कि जो लोग नियमित रूप से अपनी उंगलियां चिटकाते हैं, उनमें गठिया होने का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसलिए, यह कहना गलत होगा कि ऐसा करने से गठिया की बीमारी होती है। वैज्ञानिक नजरिए से यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो आपके जोड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती।

क्या पड़ जाती है उंगलियां चटकाने की आदत?

उंगलियां चटकाने की आदत पड़ जाती है, लेकिन इससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। यह सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है, जो आपके जोड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कई लोग इसे तनाव मुक्त करने का तरीका मानते हैं और इससे कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या नहीं होती। इसलिए, इसे हानिकारक मानना गलत होगा। हालांकि, अगर आपको किसी प्रकार का दर्द महसूस होता है तो इसे करना बंद कर दें।

कैसे छोड़ी जा सकती है यह आदत?

अगर आपको अपनी इस आदत पर नियंत्रण पाना है तो धीरे-धीरे प्रयास करें। इसके लिए आप अपने हाथों को व्यस्त रखने का प्रयास कर सकते हैं या ध्यान केंद्रित करने के दौरान इसे भूल सकते हैं। साथ ही आप काम करते हुए इस आदत को रोक सकते हैं। दिनभर व्यस्त रहने की कोशिश करें और खाली बैठे-बैठे भी ध्यान रखें कि आप अपनी उंगलियां न चिटकाएं। इससे धीरे-धीरे आपकी यह आदत छूट जाएगी।

हर महिला के पास होने चाहिए ये 5 मेकअप एसेंशियल्स, आसानी से मिलेगा खूबसूरत लुक

मेकअप हर महिला की सुंदरता को निखारने में मदद करता है। सही मेकअप प्रोडक्ट्स का चयन और उपयोग करना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे मेकअप एसेंशियल्स के बारे में बताएंगे, जो हर महिला के पास होने चाहिए और जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर आप अपने चेहरे को और भी सुंदर बना सकती हैं। इन प्रोडक्ट्स का सही उपयोग करके आप अपने लुक को निखार सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं।

बेस मेकअप प्रोडक्ट्स का चयन कैसे करें?

बेस मेकअप प्रोडक्ट्स जैसे कि फाउंडेशन, कंसीलर और प्राइमर बहुत जरूरी होते हैं। फाउंडेशन आपके चेहरे की रंगत को समान बनाने में मदद करता है, जबकि कंसीलर डार्क सर्कल्स और दाग-धब्बों को छिपाने में सहायक होता है। प्राइमर त्वचा को मुलायम बनाता है और मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखता है। इन सभी प्रोडक्ट्स का सही चयन और उपयोग करके आप अपने चेहरे को बेहतरीन लुक दे सकती हैं और आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं।

आंखों की सुंदरता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स

आंखें चेहरे की जान होती हैं। इन्हें खूबसूरत बनाने के लिए आईलाइनर, मस्कारा और आईशैडो का सही उपयोग करना जरूरी है। आईलाइनर आपकी आंखों को गहरा और आकर्षक बनाता है, मस्कारा पलकों को घना और लंबा दिखाती है, जबकि आईशैडो आपकी आंखों की गहराई बढ़ाता है। इन सभी प्रोडक्ट्स का सही उपयोग करके आप अपनी आंखों को निखार सकती हैं और अपने लुक को और भी खास बना सकती हैं।

गालों को निखारने वाले प्रोडक्ट्स

गालों की रंगत बढ़ाने के लिए ब्लश पाउडर का उपयोग करें। यह आपके गालों को ताजगी भरा दिखाता है और चेहरे पर एक सुंदर चमक लाता है। ब्लश पाउडर चुनते समय अपनी त्वचा की रंगत का ध्यान रखें ताकि यह आपके चेहरे पर प्राकृतिक लगे। इसके अलावा हाइलाइटर का भी उपयोग करें, जो आपकी गालों की ऊंचाई को निखारता है और चेहरे पर एक खास चमक देता है।

होंठों को खूबसूरत बनाने वाले प्रोडक्ट्स

होंठों को आकर्षक बनाने के लिए लिपस्टिक या लिप टिंट का उपयोग करें। यह न केवल आपके होंठों को रंगता है बल्कि उन्हें नमी भी देता है। लिपस्टिक चुनते समय अपने त्वचा की रंगत और मौके का ध्यान रखें ताकि यह आपके चेहरे पर अच्छी लगे। इसके अलावा आप लिप बाम का भी उपयोग कर सकती हैं, जो आपके होंठों को नरम और स्वस्थ बनाए रखता है।

मेकअप सेटिंग स्प्रे का महत्व

मेकअप सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने में मदद करता है। इसे लगाने से आपका पूरा मेकअप सेट रहता है और आपको बार-बार टचअप की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रथम पृष्ठ का शेष

खत्म हुआ इंतजार..

पर जोर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत जिस स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है, उसकी चर्चा दुनियाभर में हो रही है। उन्होने कहा कि बीते कुछ महीनों के भीतर ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ है, साथ ही मेरठ तक मेट्रो पहुंची है, नोएडा में एयरपोर्ट शुरु हुआ है और अब दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर भी शुरु हो चुका है। इतने छोटे से क्षेत्र में इतना सबकुछ हो रहा है तो आप देशभर की प्रगति का आंकलन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में कई इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम चल रहा है। ये इकोनॉमी कॉरिडोर प्रगति के नए द्वार बनने जा रहे हैं जिनसे हमारी उम्मीदों की डोर भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली – देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से जहां लोगों का आने जाने में समय बचेगा, वहीं ईंधन की खपत कम होने से किराया और माल भाड़ा भी बचेगा। साथ ही किसानों को अपने उत्पाद, तेजी से बड़ी मंडियों तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी। इस शानदार एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ उत्तराखंड के पर्यटन को मिलेगा । बारामासी पर्यटन की ओर बढ़ा उत्तराखंड: प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार द्वारा विंटर टूरिज्म, विंटर स्पोर्ट्स और वेड इन उत्तराखंड जैसे अभियानों को बढ़ावा दिए जाने के लिए जारी प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि, अब उत्तराखंड बारामासी पर्यटन की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने 2023 में अपनी आदि कैलाश- ओमपर्वत यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि, पहले यहां साल में कुछ सौ लोग ही आते थे, जबकि 2025 में यह संख्या 40 हजार के पार पहुंच गई है। इसी तरह उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा में आने वाले पयर्टकों और तीर्थयात्रियों की संख्या भी 80 हजार से बढ़कर डेढ़ लाख पहुंच गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए, प्रगति, प्रकृति और संस्कृति को साथ रखा जाना जरूरी है। इसलिए आज हर निर्माण का इस त्रिवेणी को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ध्यान देना होगा कि इंसानों के लिए होने वाले विकास कार्यों से वन्य जीवों को कोई कष्ट न हो। इसलिए दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 12 किमी लंबा एलिवेट रोड बनाया गया है। उत्तराखंड की पवित्रता का करें पालन: प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों के साथ ही यहां आने वाले पयर्टकों से अपील करते हुए कहा कि वो देवभूमि की धरोहर बहुत पवित्र है, ऐसे स्थानों का साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य है। यहां जगह -जगह कूड़ा डालने, प्लास्टिक की बोतलें फेंकने से देवभूमि की पवित्रता को ठेस पहुंचती है। इसलिए देवभूमि के तीर्थ स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल हरिद्वार में दिव्य, भव्य और स्वच्छ कुंभ मेले का आयोजन होगा, इसी के साथ उत्तराखंड में जल्द ही नंदा देवी राजजात भी आयोजित होने वाली है। ये यात्रा उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक चेतना का भी उदाहरण है, जिसमें मां नंदा को बेटी मानकर सम्मान के साथ विदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो मां नंदा को प्रणाम करते हुए, विकसित भारत के निर्माण में माताओं बहनों की बड़ी भूमिका है। 2029 में आधी आबादी को मिलेगा पूरा हक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए, संसद ने चार दशक के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर दिया है, इससे लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण तय हो गया है। अब इसे लागू करने में देर नहीं होने चाहिए, 2029 के लोकसभा और इससे आगे के विधानसभा चुनावों में इसे लागू किया जाना चाहिए। देश की इसी भावना के अनुरूप 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने सभी दलों से इस संसोधन अधिनियम को समर्थन देने की अपील करते हुए कहा कि, 2029 में देश की पचास प्रतिशत आबादी को उनका हक मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सैन्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश, 1962 में शहीद हुए बाबा जसवंत सिंह के शौर्य को भुला नहीं सकता। सैनिकों के सम्मान के क्रम में केंद्र सरकार ने वन रैंक, वन पेंशन लागू करते हुए पूर्व सैनिकों के खाते में सवा लाख करोड़ से अधिक की धनराशि जमा की है। जिसका लाभ उत्तराखंड के हजारों परिवारों को भी मिला है। सरकार देशभक्ति, देवभक्ति और प्रगति को जोडते हुए विकसित भारत का संकल्प सच करने का प्रयास कर रही है।

मुख्य परीक्षा में 29 अभ्यर्थी सफल, 4 जून को टंकण परीक्षा और अभिलेख सत्यापन

हरिद्वार । उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने महाधिवक्ता कार्यालय नैनीताल में समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें कुल 29 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के सचिव अशोक कुमार पांडे ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। मुख्य परीक्षा का आयोजन इसी साल 31 जनवरी को किया गया था। परिणाम के अनुसार समीक्षा अधिकारी पद के लिए 14 और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए 15 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। सफल अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित टंकण परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन 4 जून को आयोग कार्यालय में आयोजित किया जाएगा।

आंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक

हरिद्वार । राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण समिति की पूर्व राष्ट्रीय सचिव रेखा नेगी ने डॉ. आंबेडकर की जयंती पर लोगों से उनके विचारों से सीख लेने की अपील की। उन्होंने बताया कि अंबेडकर के विचार आज भी सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। देशभर में स्थापित स्मारक, संग्रहालय, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय उनकी विरासत को संजोए हुए हैं। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष और सफलता की प्रेरक मिसाल है, जो आज भी समाज के वंचित वर्गों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है।

चारधाम यात्रा के आपदा सुरक्षित संचालन के लिए उत्तराखण्ड को हर सहयोग देगा एनडीएमए: कृष्णा वत्स

देहरादून (संवाददाता)। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में चारधाम यात्रा के दौरान संभावित आकस्मिकताओं एवं आपदा की स्थिति में प्रभावी रूप से निपटने हेतु एक विस्तृत टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष कृष्णा एस वत्स ने टेबल टॉप एक्सरसाइज की अध्यक्षता करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा केवल उत्तराखण्ड राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। गृह मंत्रालय एवं भारत सरकार का विशेष फोकस इस यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न कराना है, जिसके लिए एनडीएमए द्वारा राज्य को हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने चारधाम यात्रा के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यात्रा मार्गों पर जोखिम आकलन को और अधिक बहुआयामी बनाया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत रूट स्पेसिफिक रिस्क मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा संभावित खतरों के दृष्टिगत एंटीसिपेटरी एक्शन (पूर्वानुमान आधारित कार्यवाही) को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी धामों की कैरिंग कैपेसिटी का समुचित ध्यान रखा जाए तथा माइक्रो लेवल पर विस्तृत रिस्क असेसमेंट किया जाए। संवेदनशील एवं जोखिमयुक्त स्थानों (हॉटस्पॉट्स) की पहचान कर वहां के लिए विशेष एवं ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। साथ ही यात्रियों तक समयबद्ध एवं प्रभावी एलर्ट पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि वे स्वयं भी आवश्यक सुरक्षात्मक कदम उठा सकें।

श्री वत्स ने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग को अपनाने पर विशेष बल दिया तथा कहा कि इससे संभावित आपदाओं के प्रभाव का बेहतर पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। उन्होंने क्राउड एवं ट्रैफिक मैनेजमेंट को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए इसके लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर बल देते हुए उन्होंने मोबाइल हेल्थ यूनिट्स की संख्या बढ़ाने को कहा। साथ ही हेली सेवाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने तथा सभी हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जिससे किसी भी प्रकार की हेली दुर्घटना को रोका जा सके। इस अवसर पर सचिव, एनडीएमए एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भारत सरकार मनीष भारद्वाज ने कहा कि चारधाम यात्रा के प्रबंधन एवं संचालन में उत्तराखण्ड राज्य ने एक बैंचमार्क स्थापित किया है। उन्होंने यात्रा को लेकर राज्य सरकार द्वारा अपनाए जा रहे दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के समन्वित प्रयासों से ही इस प्रकार की बड़ी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से शून्य मृत्यु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश

दिए कि यात्रियों के मोबाइल फोन में सचेत एप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड कराया जाए, ताकि समय पर चेतावनी एवं अलर्ट संदेश प्राप्त हो सकें और किसी भी संभावित जोखिम से बचाव सुनिश्चित किया जा सके। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए राज्य सरकार तथा यूएसडीएमए द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनडीएमए का मॉक अभ्यास कराने के लिए आभार भी जताया। इस अवसर पर एडवाइजर आपरेशन, एनडीएमए, कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह, ज्वाइंट एडवाइजर आपरेशंस, ले. कर्नल एसके शाही, लीड कंसलटेंट मेजर जनरल सुधीर कुमार बहल, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन महावीर सिंह चैहान, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी, कमाण्डेंट एनडीआरएफ संतोष कुमार आदि मौजूद रहे।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को मौका दें

कृष्णा वत्स ने छोटे शहरों एवं प्रमुख पड़ाव स्थलों पर भी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों, विशेषकर एआई/एमएल के अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही तथा इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को अवसर देने का सुझाव दिया। संचार व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने हेतु उन्होंने कम्युनिकेशन ऑन व्हील्स जैसी मोबाइल संचार तकनीकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया, जिससे दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी निर्बाध संचार सुनिश्चित किया जा सके।

तैयारियों को परखने का माध्यम है मॉक अभ्यास

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत आयोजित यह मॉक अभ्यास हमारी तैयारियों को परखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। निरंतर मॉक ड्रिल्स एवं टेबल टॉप एक्सरसाइज के माध्यम से हम अपनी संस्थागत एवं फील्ड स्तर की क्षमताओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। विगत वर्षों में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इन अभ्यासों से हमें वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाने का अवसर मिला है। इनसे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित निर्णय क्षमता एवं संसाधनों के प्रभावी उपयोग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा को पूर्णतः सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं निर्विघ्न बनाया जाए। इसके लिए माइक्रो लेवल पर तैयारी, जोखिमों की पूर्व पहचान एवं समयबद्ध प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है, जिसमें ऐसे अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

काल्पनिक परिदृश्यों से परखी तैयारियां

टेबल टॉप एक्सरसाइज के दौरान लीड कंसलटेंट मेजर जनरल सुधीर बहल एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन) डीआईजी राजकुमार नेगी द्वारा जनपदों की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को काल्पनिक आपदा परिदृश्यों के आधार पर परखा गया। इस दौरान यह आकलन किया गया कि सूचना प्राप्त होते ही प्रथम प्रतिक्रिया कितनी शीघ्र एवं प्रभावी ढंग से दी गई तथा उपलब्ध संसाधनों का प्रबंधन किस प्रकार किया गया। अभ्यास के दौरान विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय, कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम की प्रभावशीलता, संचार तंत्र की सक्रियता तथा सूचना के आदान-प्रदान की गति पर विशेष ध्यान दिया गया। यह भी परखा गया कि आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, परिवहन एवं अन्य रेखीय विभाग किस प्रकार एकीकृत रूप से कार्य करते हैं और आपसी तालमेल के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्यों को किस स्तर तक प्रभावी बनाते हैं।

स्वामी,मुद्रक व प्रकाशक अवनीश कुमार द्वारा भगवती प्रिंटर्स,इण्डस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार से छपवाकर ग्रा. बसवाखेड़ी पो. मंगलौर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया।
सम्पादकः अवनीश कुमार, मो० 9410553400
ई-मेल: liveskgnews@gmail.com
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र हरिद्वार न्यायालय में ही होगा)
सभी लेखों में सम्पादक की सहमति जरूरी नही है।